हमने दाम बढ़ाकर, किसानों को अधिक देकर किसानों को फ़ायदा पहुंचाया है। लेकिन वास्तविकता इसके विरुद्ध है। इसलिये कि आपने अपने बयान में यह लिखा है कि बाजार मूल्यों का रुख मांग और आपूर्ति और आदान मूल्यों में परिवर्तन, अन्तर फ़सल मूल्य समानता, इन तीनों चारों चीजों को ध्यान में रख कर हमने दामों को जो पिछले समय तय किये गये थे उनको बढ़ाया था। जब यह बात आती है महोदय, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस समय जो आपने तिलहन, दलहन, चने आदि के दाम कहीं 20-25 और 55 रुपये बढ़ाये हैं, इनमें निश्चित रूप से जो बाजार में बढ़ते हुये दामों का रुख था उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि आज जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा सरसों के तेल का दाम 32 रुपये, चने का दाम 14 रुपये, दलहन तिलहन का दाम 14 रुपये हैं, इसमें आपने दिया है 400 रुपये। तीन गुना दाम इधर बढ़े हैं। अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होता इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में वे आगे जब इस पर विचार करेंगे तो बाजार में जिस तरह से इन चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं किसानों के घर से निकलने के बाद, उस का भी ध्यान रखा जायेगा या नहीं रखा जायेगा। दूसरी बात यह है कि छोटे-छोटे किसान बेचारे गरीब हैं, छोटी खेती है। वे तो जो पैदा करते हैं बाजार में तुरन्त बेच देते हैं और अपना काम चलाते हैं। उनको ये दाम मिल नहीं पाते हैं। इस लिये गरीब किसान जो मजबूर होकर बेचते हैं वे अपनी फ़सल का दाम नहीं पाते हैं, जिनका शोषण होता है, इसको रोकने के लिये सरकार के पास क्या योजना है?

श्री सभापति: डिस्ट्रेस सेल न करनी पड़े।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: छोटे किसानों के लिये कि वे मजबूरी में बेच न पाये, मैं वेयर हाउसिंग के बारे में पहले ही उत्तर दे चुका हूं और पी.डी. सिस्टम भी जो है उसका विस्तार किया जाय; जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको बेचना पड़ता है उनके बारे में पहले कह चुका हूं। दलहन और तिलहन के भावों के बारे में कहा गया। खास तौर से इसमें कमी है पूरे उत्पादन की और इस दिशा में बाहर से भी जो मंगाते थे, हम लोग, उन देशों में भी अब दाल खाने का रिवाज कम हो रहा है तो उनसे, बाहर से भी मंगाने में कमी आती है, गोया इसको ओ.जी.एल. पर भी रखा गया है। खास तौर से प्रयास इस दिशा में करना है कि इसका उत्पादन बढ़े, दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़े और रिसर्च पर रिसर्च की जा रही है कि इसकी उत्पादकता बढ़ायी जाय। दामों के बढ़ते में केवल अगर गेहूं के दाम बढ़ते जायें और दलहन तथा तिलहन के रिलेटिव प्राईस दबे रहेंगे तो जो हम कराना चाहते हैं और जो हम आत्मनिर्भरता ले आना चाहते हैं दलहन और तिलहन पर नहीं हो सकती है। जब अच्छे दाम मिलेंगे तो उससे ज्यादा करके उसके भाव में स्थायित्व आयेगा।

*222. [*The questioner (Shri Ghufran Azam) was absent. For answer* vide *col. infra*].

Blueprint for model villages in the country

*223. Shri S. Madhavan: Will the Minister of AGRICUTURE be pleased to state:

(a) whether Government are preparing a Blueprint for fully equipped model villages with piggery, roller mill, farmers houses in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether the former Agriculture Minister had sought any help from the Chinese Government to promote such villages in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of reply at (a) above.

(c) No, Sir.

SHRI S. MADHAVAN: Sir, is it a fact that when the former Agriculture Minister went to China, he visited a number of villages which were fully-equipped model villages. If so, what kind of development did our officers see in those villages? For example, China has developed a new variety of paddy to boost the harvest. What are the details that have been gathered ? Is it also a fact that the former Agriculture Minister discussed with the Chinese Government officials the question of undertaking such developmental activities in our country also?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, चीन यात्रा के दौरान उप प्रधान मंत्री के साथ अधिकारीगण भी थे और जब वह वहां गये थे, तो इन लोगों ने वहां के षि विकास को देखा। तो यह तय हुआ कि कई क्षत्रों में परस्पर सहयोग की जरूरत है।

उसके संबंध में पूरा जो सहयोग का ब्यौरा हो सकता है, एक दूसरे के साथ, उसका ब्यौरा लम्बा है। इसलिये उसे मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। षि के संबंध में कई चीजें हैं, चावल के संबंध में हैं, पशु-पालन के संबंध में हैं। वह हमसे कुछ लेना चाहते हैं। फ़िर फ़िशरीज के संबंध में है। हम उनसे लेना चाहते हैं और वह हमसे लेना चाहते हैं। कई प्रकार की चीजें हैं। हाईब्रिड के संबंध में है, जर्म प्लाज्मा के संबंध में है।

श्री सभापति : आप उस पर विचार कर रहे हैं। अभी कोई माडल विलेज बनाने का इरादा नहीं है।

श्री नितिश कुमार : एक ही बात थी कि वहां यह तय हुआ था कि उन लोगों की एक टीम यहां आएगी। तो वह टीम नहीं आई है। बजाय इसके, उन्होंने अनुरोध किया है कि यहां से एक टीम जाये। तो इसके बारे में अभी कोई डट तय नहीं हुई है।

श्री सभापति : जो आपकी टीम जायेगी, तो माडल विलेज पर भी विचार करेंगे।

श्री नितिश कुमार : हां, माडल विलेज के बारे मे कोई विचार अभी सरकार में नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : बस बात, खत्म।

SHRI S. MADHAVAN: The present Government is committed to the development of the rural sector. Migration of agricultural workers and other people from the villages to the cities must be prevented. That is why I asked a specific question. In their schemes for developing the rural sector, I would like to know whether the Government will consider the question of setting up such villages where all facilities will be given to the people so that the migration of the rural population to the cities can be prevented?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय यह अलग से इस आदर्श ग्राम जैसी चीज, जो चीन में है, उस प्रकार से करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार में नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है कि गांव के मजदूर जो शहर की ओर भागते हैं, उनको रोकने के लिये गांव में ही उनको अधिक से अधिक रोजगार मिल जाए, इसके लिये सरकार कई प्रकार की योजनायें चलाती है और चलाने का विचार है और खेती की तरक्की के लिये भी कई योजनायें एक्सटेंशन के संबंध में सरकार चलाती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को गांव में ही काम मिल जाए और वह शहर की तरफ नहीं भाग सकें, और कृषि के अलावा एग्रीकल्चर के एलाईड सेक्टर में भी लोग खप सकें, इसका प्रयास भारत सरकर कर रही है।

कुमारी सईदा खातून : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यह जो सुसज्जित ग्रामों की रूपरेखा तैयार की जा रही है, तो उसमें गांव के किसानों के पास जो जानवर रहते हैं, जैसे, गाय भैंस और बकरी इत्यादि, इनके लिए कोठों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं ? क्या ऐसा प्रावधान है कि नहीं, क्योंकि वैसे किसानों के खेतों को भी यही बर्बाद करते हैं ?

तो इनके लिये ग्रामों में, हर गांव में कांजी हाऊस बनाने की व्यवस्था रखी गई है कि नहीं ?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, पशुपालन विकास के लिये बहुत योजनायें हैं डेरी क्षेत्र में और कई तरह की सहायता भी दी जाती है। लेकिन जहां तक सवाल है माननीय सदस्या ने जो कहा उसका तो गांव में बनाने का काम, इसको हमारे यहां फाटक कहा जाता है, राज्य सरकारों का है। राज्य सरकार अगर चाहें तो कर सकती है।

SHRI P. K. KUNJACHEN: I have had the chance of going to China. I visited a number of villages there. (*Interruptions*). No, no, not with Mr. Devi Lal. There they have got all round development programmes for villages. They are trying to see that there is no difference between a town and a countryside. All the facilities which are available in cities and towns are being made available in the villages also. So, are you going to develop villages keeping the above concept in view? Unless our villages are developed on those, lines, the influx of the people from countryside to the towns cannot be avoid. The must have the security of job. In the village they will have to cultivate land. (*Interruptions*). Will the Government think of finding such a solution

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, मैंने पूर्व में बताया था कि चीन के पैटर्न की नकल करने का कोई विचार नहीं है लेकिन जहां तक सवाल है गांव के विकास का और गांव के लोगों को अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का तो वर्तमान सरकार की नीति है कि बजट का आधा पैसा खेती और गांव के विकास पर खर्च किया जाए। अष्टम पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की कई योजनायें आ रही हैं जिससे शहर की तरफ भागने की जो प्रवृत्ति है लोगों में उसमें नियंत्रण हो सकता है।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Sir, a modern village may not much affect the entire gamut of things, but one important thing that has to be given priority is disbursement of industry in rural areas. Both agro-industry as well as cottage and other industries have to be given priority. Will the hon. Minister consider this particular aspect so that the rural poor will get total employment in their own village?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले ही बताया कि गांव के विकास और खेती के विकास के लिये बजट का आधा पैसा खर्च किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार की योजनाओं पर विचार किये जाने का प्रस्ताव है। अष्टम पंचवर्षीय योजना में भी कई इस प्रकार की योजनायें आ रही हैं जिसमें लोगों को गांव के स्तर पर अधिक से अधिक खपाया जा सके।

Population covered by the Public Distribution System

*224. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the total population catered by the Public Distribution System (PDS);

(b) the rural population catered by the PDS out of the above;